JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सतत विकास के लक्ष्य एवम उनके क्रियान्वयन की चुनौतियां

प्रो नंदलाल मिश्र
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय
विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना म प्र

शोध सार

विकास एक गत्यात्मक संप्रत्यय है जो अहरनिश चलता रहता है।यदि विकास चलता न रहे तो दुनिया ठहर जायेगी और दुनिया के ठहरने का अर्थ सभी को ज्ञात है। हां इसकी चाल कभी सीधी होती है तो कभी टेढ़ी मेढी हो जाती है।कभी यह धीमी गति से चलता है तो कभी बहुत तेज हो जाता है।विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जमाने में विकास की गति बहुत तेज हो गई है।जो राष्ट्र विज्ञान की समझ में अधिक रुचि लेता है वहां नए नए आविष्कार होते हैं।नवाचारों का बोलबाला रहता है किंतु जो राष्ट्र अपने परंपरा और पुराने विचारों से चिपके रहना चाहते हैं वहां इसकी गति मंद रहती है।हालाकि वैश्वीकरण ने सभी देशों को आपस में जोड़ दिया है और सबके आविष्कार एक दूसरे के सामने परिलक्षित हो रहे हैं।

औद्योगीकरण ने विकास के रास्ते में जहां एक तरफ सहजता का बीजारोपण किया है वहीं दूसरी तरफ कुछ पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा की है। आज ओजोन परत, नुकसानदायक गैसे, धरती का बढ़ता तापमान तथा मौसमी असंतुलन जैसी नाना समस्याएं हमारे सामने आ खड़ी हुई हैं।विकास ने ऐसे ऐसे कार्य कराए हैं जो अकथनीय है।एक सड़क बनाने के लिए सैकड़ों वर्ष पुराने भारी भरकम हजारों पेड़ काट दिए जाते हैं जिनको उगाने में पीढ़ियां खप गई हैं उनको पांच मिनट में काट कर फेंक दिया जाता है।जो पेड़ हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देते थे और कार्बन डाई ऑक्साइड अवशोषित करते थे उनमें भरपूर कमी आ गई।फर्नीचर के नाम पर जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं।इन कार्यों ने हमारे वातावरण को इस कदर प्रभावित किया है कि आज प्रकृति अपना हिसाब मांग रही है और हम सतत विकास के लक्ष्यों को निर्धारित करने में लगे हैं।इस आलेख में इन्ही बिंदुओं को केंद्र में रखकर चर्चा की गई है।

की वर्ड्स : सतत, संधृत, भूमंडलीकरण, विचार, सहस्त्राब्दि

प्रस्तावनाः

पूरे विश्व में विकास की होड़ है।बर्चस्व की लड़ाई है और नई नई तकनीक से एक दूसरे पर आधिपत्य की ललक है।कभी चीन तो कभी अमेरिका कभी रूस तो कभी इजरायल आधिपत्य के चक्कर में उलझे हुए हैं।भौतिक और रक्षा संबंधी उपकरणों की होड़ मची है।इक्कीसवीं सदी में सूचना प्रौद्यौगिकी ने जोर पकड़ा और पूरा विश्व इधर घूम गया।इन उत्पादों को बनाने और उन्हें उपयोग में लाने से पर्यावरणीय

असंतुलन इस कदर बढ़ गया है कि मौसम ने अपना स्थान बदल दिया है।प्रकृति दिन रात असंतुलित हो रही है और इस असंतुलन के परिणाम को मानव झेल भी रहा है।

बढ़ती हुई आबादी और सिकुड़ती जमीन सभी का पेट भरने में असमर्थ हो रही है।नतीजतन विकास ही एक ऐसा विकल्प बचता है जो लोगो को जीवन यापन करा रहा है।किंतु इसका पश्चात वर्ती प्रभाव विकास के तरीकों पर पुनर्विचार मांगता है।इसी की चिंता से सतत विकास की अवधारणा बलवती हुई और मानव यह सोचने पर विवश हुआ कि विकास तो अवश्यंभावी है पर विकास की अवधि सुदीर्घ जीवी हो न कि अल्प अवधि की।यदि यह दीर्घजीवी होगा तो इसके नुकसान को एक बार ही झेलना होगा किंतु यदि एक ही कार्य को बार बार किया जाएगा तो उसके दुष्परिणाम भी बार बार सामने आएंगे।

भौतिक विकास की चकाचौंध ने मानव सभ्यता को काल कोठरी में धकेल रखा है और दिनरात ऐसे ऐसे निर्माण कार्य चल रहे हैं जो आवश्यक नही पर मनोवैज्ञानिक रूप से अनिवार्य है।अधोसंरचना का विकास तो जरूरी है पर पिज्जा और बर्गर मंचूरियन का प्रचलन और अधिकाधिक खपत किस बात की तरफ इशारा करता है।हथियारों की होड़ और उसका अत्याधुनिक मॉडल बनाकर विश्व बाजार में उसका सौदा करना किस बात की तरफ इशारा। करता है।क्या इसे संतुलित विकास का नाम दिया जा सकता है।विश्व के देश नए नए सामग्री का निर्माण कर एक तरफ व्यापार को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ असंतुलन को निमंत्रण दे रहे हैं।इस असंतुलन के कारण बाढ़, सूखा,महामारी,अशुद्ध वायु प्रदूषित जल दुर्घटनाएं इत्यादि की आवृत्ति में वृद्धि हुई है।इससे यह आशय नही लेना चाहिए कि विकास सिर्फ गलत और ऋणात्मक प्रभाव ही उत्पन्न करता है।विकास ने अनेक संभावनाओं के द्वार खोले हैं और हमारे सामने विकल्प भी प्रस्तुत किए हैं।जरूरत है सही विकल्प के चुनाव का।विकास ने हमारे लिए एक दायरा प्रस्तुत किया,इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ हमारी मनोवृति को मोड़ा जिससे अत्याधुनिक खोजें संभव हो सकीं,हम दुनिया के सामने सीना तानकर खड़े हो रहे हैं,हम प्रबल प्रतिस्पर्धी होकर उभर रहे हैं।

आवर कॉमन फ्यूचर और प्रभाव

ब्रूटलैंड की रिपोर्ट ''आवर कॉमन फ्यूचर''के प्रकाशित होने के बाद सतत विकास, विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे चिंतकों के बीच चिंतन का प्रमुख संप्रत्याय निकलकर सामने आया हालाकि इस पर छिट पुट चर्चा 1970 के बाद से ही शुरू हो गई थी,जब मॉरिस स्ट्रॉन्ग एवम आई सैक्स ने इको डेवलपमेंट की अवधारणा प्रस्तुत की।पारिस्थितिकी के संदर्भ में सतत विकास का आशय यह है कि आर्थिक वृद्धि की अंधी दौड़ में बिगड़ते हुए पर्यावरणीय स्थिति में सुधार लाना तथा मानव के लिए उसे वहनीय बनाना सतत विकास है।सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सतत विकास वह विकास है जिसको बार बार परिभाषित करते हैं कि ''वांछित सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, संस्थाओं, संस्कृति अथवा अन्य सामाजिक विशेषताओं को संतुलित बनाए रखने की क्षमता ही सतत विकास है।

समग्र रूप में सतत विकास की मूल भावना यह है कि ''मानव के लिए वांछित जरूरतें समयानुसार पूरी होती रहें जिससे आने वाली पीढ़ियों के सामने विकल्प के रास्ते बंद न हों।उनको चुनने का विकल्प

उपलब्ध हो।हमे उतना ही उपभोग करना है जिससे आने वाली जनसंख्या को प्रतिकूल परिस्थिति का सामना न करना पड़े।इस प्रकार सतत विकास आज के बदलते प्रौद्यौगिकी मापदंडों के बीच भविष्य की चिंता करता है।

सतत विकास का एजेंडा 21 इसको स्पष्ट करते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, निर्धनता उन्मूलन, ग्राहकी के प्रतिरूप मे परिवर्तन, स्वास्थ्य, वातावरण की सुरक्षा, भूमि संरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण, पेय जल की शुद्धता पर बल, विषैले पदार्थों पर नियंत्रण, महिलाओं की सहभागिता, आदिवासी समाज को बनाए रखना, प्रौद्यौगिकी हस्तानांतरण, शिक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता में वृद्धि, सतत विकास के संदर्भ में सूचना केंद्र स्थापित करना इत्यादि कार्यक्रमों पर विशेष बल देता है। इसको देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मानव ने जिस प्राकृतिक संतुलन को छेड़ना शुरू किया था आज वही मानव अपनी गलती सुधारना चाहता है। विकसित राष्ट्रों ने प्राकृतिक संसाधनों का जिस प्रकार दोहन किया था और कर रहे हैं वह प्रकृति के साथ धृष्टता है आशाजनक पक्ष यह है कि विकसित राष्ट्र अपने उच्चतम उपभोग के बाद इस बिंदु पर पहुंचे और विकास शील तथा अविकसित राष्ट्र अंतर्द्वंद्व के सहारे इस चर्चा के प्रमुख अंग बने है।

इस असंतुलन से भूमंडल पर नानाविध घटनाएं जो कल्पनीय नही थीं, घटने लगीं। हाहाकार मचा और विश्व स्तर पर बैठकें शुरू हुईं। इस परिप्रेक्ष्य में प्रो एस सी दुबे (1996) ने एक टिप्पणी की जो बेहद सटीक प्रतीत होती है ''झूठे साबित हुए या न पाए जा सके आदर्शों की एक बड़ी श्रृंखला को अपने पीछे छोड़ विकास का तिलिस्म टूट चुका है। विकास के क्लासिकी अभिकल्प के टूटने से गंभीरतापूर्वक पुनर्विचार और विकल्पों की खोज आवश्यक हो गई है।विकास के वैकल्पिक प्रतिरूप को उस समय गहरा धक्का लगा जब सोवियत संघ अपनी आर्थिक विफलताओं को स्वीकार करता हुआ विखंडित हो गया।'' प्रो आर के मणि त्रिपाठी (1996) लिखते हैं''लगता है टीन कनस्तर और इसी तरह की ढेर सामग्री से भरे बंद अंधेरे कमरे में कोई राह ढूढने की कोशिश कर रहा है और चलने की हर कोशिश टीन और कनस्तर की खड़खड़ाहट ही पैदा करती है....एक अर्थहीन बेसुरा शोर। संतोष है इस बात का कि कोई चल रहा है चल तो रहा है।'' सुधीश पचौरी (1996) को भी इस विकास से छटपटाहट है और वे बरबस कह उठते हैं ''अपने समाज में मौजूदा उपद्रव बहुत आधुनिक और उत्तर आधुनिक की टकराहटों का नतीजा है। अपने यहां बहुत कुछ पूर्व आधुनिक स्थितियां भी मौजूद हैं जो उत्तर आधुनिक स्थितियों में पंड्य बना रही हैं। यह तिहरी गांठ हैं जो तेजी से खुल रही है। अपनी आधुनिकता अचानक अनाथ हो उठी है। यह अनाथत्व हमारी अपनी उत्तर आधुनिकता का प्रस्थान बिंदु है जो विकास के समूचे नक्शे पर पुनर्विचार मांगता है। अफसोस यह है कि यहां से पूर्व पूंजीवाद में लौटा नही जा सकता और आगे जाने की राह उतनी ही बनती है जितनी बनाई जा सके।''

इन्ही स्थितियों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए भारत वर्ष में विकास का एक खाका तैयार किया गया और इसका नाम दिया गया ''सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (MDG)। इस लक्ष्य के प्रमुख बिंदु थे.....

- भुखमरी तथा गरीबी को दूर करना

- शिशु मृत्यु दर को कम करना
- मातृत्व स्वास्थ्य को दुरुस्त करना
- सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करना
- लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण
- संरक्षित पर्यावरण
- वैश्विक विकास और मधुर संबंध
- मलेरिया, एड्स टीवी जैसी बीमारियों से छुटकारा पाना

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य

चूंकि प्रत्येक राष्ट्र को अपने देश के विकास की समीक्षा समय समय पर करनी होती है और उसे विश्व पटल पर रखना होता है।भारत सरकार ने भी पहली बार अपने वैकासिक समीक्षा को सन् 2017 में न्यूयार्क में उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर रखा और अपने प्रगति को बताया। यह प्रगति सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के अंतर्गत वर्ष 2000 से वर्ष 2015 के बीच की थी। इस बीच में जो भी विकास के कार्य संपन्न हुए उसका लेखा जोखा न्यूयार्क में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70 वीं बैठक में आने वाले 15 सालों के लिए सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए। इस एजेंडे को औपचारिक तौर पर सभी राष्ट्र सदस्यों ने अपनाने का निर्णय लिया। बहुत सारे कार्यों को सहस्त्राब्दि लक्ष्य में पूरा किया गया लेकिन बहुत कुछ अभी छूटा हुआ है जिसे सतत विकास के लक्ष्य में सम्मिलित कर लिया गया है। यहां यह जानना आवश्यक है कि सतत विकास के जो मोटे 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए वो क्या हैं तथा हम अभी कहां पहुंच पाए हैं।

सतत विकास के लक्ष्य और चुनौतियां

सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की हाई पावर कमेटी में इसे तैयार किया गया तथा 193 देशों ने इसे अंगीकृत किया जिसमे भारत भी सम्मिलित रहा। इसका नाम दिया गया ''ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड : 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट''। एक जनवरी 2016 से इसे क्रियान्वित भी कर दिया गया। इसके लक्ष्य निम्लिखित निर्धारित किए गए.....

1. पूरे विश्व से गरीबी को दूर करना
2. खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और संधृत कृषि के उपाय करना
3. स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन
4. समावेशी शिक्षा पर बल,गुणात्मक शिक्षा में वृद्धि और सभी के लिए अवसर
5. लैंगिक बराबरी एवम महिला सशक्तिकरण
6. स्वच्छता और जल प्रबंधन
7. सस्ती,विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा तक सभी की पहुंच
8. समावेशी और सतत आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार तथा अच्छे कार्य को प्रेरित करना

9. समावेशी और अक्षय औद्योगीकरण में वृद्धि तथा बुनियादी ढांचे को समृद्ध करना
10. देश के अंदर एवम अन्य देशों के साथ असमानता में कमी लाना
11. मानव बस्ती निर्माण,और सुरक्षित शहरों की व्यवस्था
12. उत्पादन प्रक्रिया और मांग में संतुलन बनाना
13. जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों को समझना एवम तत्काल समाधान तलाशना
14. विकास के लिए महासागरों,समुद्रों के संसाधनों का संरक्षण एवं उपयोग
15. धरातलीय पारिस्थितिकी प्रणाली को सुदृढ़ करना जंगलों का संरक्षण एवं जैव विविधता के दुष्प्रभाव को कम करने का प्रयास
16. विश्व स्तर पर सभी को न्याय प्राप्त करने हेतु समितियों का गठन एवम उन्हे जबाबदेह बनाना
17. सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को बढ़ाना

ये लक्ष्य सतत विकास को स्थाई बनाने के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्रसन्नता इस बात की है कि उन देशों को भविष्य की चिंता हुई है जो सर्वप्रथम जिम्मेदार हैं प्रकृति के विनाश की।विकास और अधिकाधिक भंडारण के फेर में इन देशों ने जिन स्थितियों को विश्व के सामने ला खड़ा किया है वे निसंदेह त्वरित विचारणीय हैं। सतत विकास के ये लक्ष्य 2030 तक कितने पूरे होंगे ये तो नही बताया जा सकता किंतु रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध ,चीन का उन्माद और प्रकृति की विनाशलीला जो कोरोना के रूप में विश्व के सामने प्रस्फुटित हुई है वह पूरे विश्व मानव को संदेश देने के लिए काफी है कि हे विश्व के प्रतिस्पर्धियों सुधर जाओ केवल योजना मत बनाओ अपितु अपने दायरे में रहो अन्यथा प्रकृति तो अपनी लीला करेगी ही करेगी।वह अपने को संतुलित करेगी भले उसे इंसान को भी नियंत्रित करना पड़े।

सतत विकास के लक्ष्यों पर भारतीय प्रगति

सन 2016 से भारत ने इन लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत से कार्य किए हैं।विकास की नीतियां बनाते समय यथासंभव उन लक्ष्यों को शामिल करने का प्रयास किया जाता रहा है। गरीबी दूर करने के विभिन्न प्रयास हो रहे हैं।किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा पैसा मिल रहा है। गरीबों के कल्याण के लिए शौचालय, आवास और उन्हें खाद्यान्न दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, डिजिटल इंडिया, पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बुनियादी सुविधाओं पर जोर तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इत्यादि कार्यक्रम सतत विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इतना सब करने के बाद भी भारतीय प्रयास की सराहना उचित नहीं है क्योंकि हम अभी बहुत पीछे हैं। यों तो सरकार विकास के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है जैसे कृषि क्षेत्रों में नवाचार, अधोसंरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन, स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति और आर्थिक क्षेत्रों में लचीलापन इत्यादि कार्य सराहनीय कहे जा सकते हैं किंतु राष्ट्रीय जरूरतों के हिसाब से बहुत सारे संसाधनों के लिए हमे दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ता है। हम विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं पर वांछित दिशा में प्रयास नाकाफी हैं।

हमारे युवा और उनकी कार्यक्षमता अन्य देश के लोगों से अधिक अच्छी है पर रोजगार को लेकर उनमें संशय है। हम व्यवस्थित कार्यक्रम नही बना पा रहे। एक आध क्षेत्रों में काम बहुत अच्छे हो रहे हैं पर सरकार और जनता के बीच विकास पर खुले विचारों की कमी है।हालाकि लोगों की क्रयशक्ति बढ़ी है पर वह स्थाई न होकर पानी के बुलबुले जैसा है।

राष्ट्रीय स्तर पर पक्ष और विपक्षी दलों में एकरूपता नही है। देश की आर्थिक प्रगति पर सामंजस्य नहीं है। इसके चलते हम सतत विकास के लक्ष्य को कितना हासिल कर पाएंगे यह कहना जल्दीबाजी होगी हालाकि अब मात्र 6 वर्ष ही शेष हैं। अतः हमे सभी लोगों को साथ लेकर इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना होगा।

समीक्षात्मक टिप्पणी

वास्तव में देखा जाय तो भारत अपनी विशालता के चलते लक्ष्यों को उस गति से प्राप्त नहीं कर पाता जितनी वह कोशिश करता है।लेकिन भारतवर्ष की जो कटिबद्धता है वह विश्वसनीय है।दरअसल भारतीय विकास सतत विकास के मार्ग का अनुसरण करता है और पूर्व में जितने भी विकास के कार्य होते थे उनमें सातत्यता पाई जाती थी। समय बदला। भूमंडलीकरण का दौर आया। विश्व के देश एक दूसरे के करीब आए।सूचना क्रांति ने देशों की दूरियां कम कर दीं। इसके चलते विकसित और विकास शील राष्ट्रों में यूज और थ्रो की संस्कृति विकसित हुई। यूज और थ्रो के प्रबल उपयोग से ही विकास की संधृतता प्रभावित हुई और हम सतत विकास की तरफ सोचने को बाध्य हुए। अब जबकि सतत विकास का एजेंडा सेट हो चुका है और लागू हो चुका है। बहुत सारे देश उस एजेंडे पर काम तेजी से कर रहे हैं पर भारत वर्ष की राजनीतिक स्थितियां इस कदर लिबरल हैं कि किसी भी सरकार को विकास का एजेंडा लागू करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ केंद्रीय योजनाएं अपना कार्य करती हैं तो वहां राज्य सरकारों का हस्तक्षेप झेलना पड़ता है।किसी राज्य में उसी पार्टी की सत्ता है जिसका केंद्र में है तो दूसरी तरफ कई राज्यों में दूसरे दलों की सरकार है। वे केंद्र सरकार से विकास का बजट ही मांगते रह जाते हैं।

तीसरी स्थिति में गठबंधन की सरकारें भी काम कर रही हैं जिनका आपस में तालमेल ठीक ढंग से नहीं बन पाता और वैकासिक योजनाएं पूरी नहीं हो पातीं। फिर भी हम विकास के लक्ष्यों की तरफ तेजी से बढ़े हैं पर अभी हम इसमें बहुत पीछे हैं। हमें समन्वित प्रयास की जरूरत है अन्यथा भारत काफी पीछे रह जायेगा।

संदर्भ

- कृष्ण कुमार (1996), विचार का डर, राजकमल प्रकाशन दिल्ली।
- त्रिपाठी, आर,के एम (1982) रीडिंग मैटेरियल, ए कलेक्शन ऑफ पेपर्स, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (1996), देसाई ए आरःसोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नालिस्म,बांबे पॉपुलर पब्लिकेशन।
- दुबे, एस सी (1999) विकास का समाजशास्त्र,वाणी प्रकाशन,नई दिल्ली।

- पचौरी,सुधीश (1996) रीडिंग मैटेरियल्सः ए कलेक्शन ऑफ पेपर्स,एकेडमिक स्टाफ कॉलेज गोरखपुर।
- मिश्रा, एन एल (1996) रूरल डेवलपमेंट, श्री प्रकाशन न्यू दिल्ली।
- मिश्रा, एन एल (2000) विकास की चुनौतियां एवम अंतर्द्वंद, शर्मा प्रकाशन, आगरा।